

(M)

नियोजित सामाजिक परिवर्तन

गुन्नार मिर्डल के अनुसार नियोजन किसी देश की सरकार द्वारा किए गए वे जागरूक प्रयास हैं जिनके द्वारा लोकनीतियों को अधिक तार्किक ढंग से समन्वित किया जाता है ताकि अधिक तेजी से विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाए। सामाजिक नियोजन चेतन रूप से लिया गया निर्णय है जिसमें कोई भी समाज पहले अपनी समस्याओं को पहचानकर उसे अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर सूचीबद्ध करता है फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिये अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करता है और अपने संसाधनों को देखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्यक्रम बनाता है। स्पष्ट है, समस्याओं की पहचान से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक सभी स्तर पर सोच विचारकर कदम उठाने की प्रक्रिया ही नियोजित सामाजिक परिवर्तन कहलाती है।

★ नियोजित परिवर्तन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि विवेकपूर्ण ढंग से योजना का निर्माण किया जाए ताकि विकास के लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि योजना बनाते समय राष्ट्र की परिस्थितियों का समुचित मूल्यांकन किया जाए। यदि राष्ट्र पर युद्ध की विभीषिका मँडरा रही है तो नियोजन की रणनीति अलग होगी और यदि शांति की स्थिति है तो नियोजन का स्वरूप भिन्न होगा। इसी तरह, यदि देश क्षेत्रवाद, आंतकवाद जैसी परिस्थितियों से संघर्षरत है और विघटन को महसूस कर रहा है। तो नियोजन की रणनीति कुछ और होगी और राष्ट्र की स्थिति ऐसी है जहां पर गरीबी, भ्रष्टाचार आदि फैला है तो वहां नियोजन की रणनीति अलग होगी।

नियोजन की रणनीति निर्धारित करते समय यह भी आवश्यक है कि राष्ट्र के सामान्य मूल्य तथा विचारधारा को ध्यान में रखा जाए और उसी के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए। नियोजन का स्वरूप सरकार की विचारधारा से भी निर्धारित होता है। उदाहरणतः यदि सरकार समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है तो नियोजन की रणनीति पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित रणनीति से भिन्न होगी।

अगले स्तर पर राष्ट्र भिन्न-भिन्न समस्याओं से जूझ रहा होता है उन समस्याओं की पहचान की जाती है और नियोजन करने से पहले उन समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाता है। समस्याओं की स्पष्टता इसलिए आवश्यक है कि इससे समस्या का नियोजन करने में न केवल सुविधा होती है बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति भी सरल हो जाती है। इसके अलावा, सभी लक्ष्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर इन्हें प्राथमिकताओं के आधार पर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों में वर्गीकृत करके इनको प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाते हैं।

एक नियोजक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पास आंतरिक संसाधन कितने हैं और उसे बाहर से कितने मिलने की संभावना है। इस तरह से समस्त स्रोतों से संसाधनों का आंकलन कर विभिन्न मद्दों के लिये संसाधनों का प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर आवंटन किया जाता है ताकि कोई भी क्षेत्र उपेक्षित न रह पाए।

नियोजित कार्यक्रम को सही ढंग से लागू करने के लिये इस तरह की रणनीति लागू करनी पड़ती है कि विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंच सके। नियोजन करना जहां सैद्धांतिकता का पक्ष है वहीं इसे लागू करना इसके व्यावहारिक पक्ष को दर्शाता है। फलतः, इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन नियोजन की सफलता हेतु अपरिहार्य हो जाता है। इसके अलावा, समय-समय पर अनुसंधान कार्यो द्वारा कार्यक्रम के संदर्भ में लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानना भी आवश्यक है क्योंकि इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन द्वारा न केवल कार्यक्रम में निहित खामियों का पता चलता है बल्कि लोगों की मनोवृत्तियों के अनुरूप भावी योजना को स्वरूप प्रदान करने में भी सहायक होता है।

मूल्यांकन

स्पष्ट है सामाजिक विकास या आधुनिकीकरण की दिशा में नियोजित परिवर्तन कई बातों पर निर्भर करता है जिन पर ध्यान

दिये बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। हाल के वर्षों में सामाजिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में परिवर्तन की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है। समाज वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया है कि उन्हें सैद्धांतिक परिपक्वता एवं अध्ययन पद्धति की परिशुद्धता प्राप्त हो गयी है। फलस्वरूप वे नियोजन को एक दिशा दे सकते हैं जिससे आधुनिकीकरण एवं विकास के लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया ने नियोजन की रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय मांगों के महत्व को भी बढ़ा दिया है जिसको नियोजन की रणनीति में शामिल किए बिना व्यापक संदर्भ में सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।